

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग **∏---क्षण्ड** 3---**उपलण्ड (ii)**

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384]

नहें विल्ली, बृहस्पतिजार, भ्रास्त 24, 1972/भाद्र 2, 1894

No. 3841

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 1972/BHADRA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August 1972

S.O. 563(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into the definite matters of public importance hereinafter specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry, consisting of Shri Vyas Dev Misra, a Judge, High Court of Delhi, to inquire into the following matters, namely:

- (a) the course of disturbances which took place at Shahdara and elsewhere in Delhi from the 19th August, 1972, to 22nd August, 1972, following the alleged murder of Shri Onkar Singh, on the 18th August, 1972; (b) adequacy of administrative measures taken to prevent and deal with the said disturbances;
- (c) justification for the use of force by the police and the extent thereof; (d) allegations of excesses, if any, by the police; and
- (e) any other matter having relevance to the above.

The Commission shall make every endeavour to complete its inquiry and make its report to the Central Government by the 31st December, 1972;

And whereas the Central Government is of opinion that having regard to the nature of inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission, the Central Government hereby directs under sub-section (1) of the said section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

INo. 31/6/72-Poll.I.1

गृह मंत्रालय

प्रधिसूचना

मई दिल्ली, 24 श्रगस्त, 1972

का॰ ग्रा॰ 563 (ग्र).—यतः केन्द्रीय सरकार का मत है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों की, जिनका उल्लेख ग्रागे किया जा रहा है, जांच के उद्देश्य से एक जांच ग्रायोग नियुक्त करना भावश्यक है;

श्रतः श्रव, जांच श्रायोग श्रिधिनियम, 1952(1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंग्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक जांच श्रायोग नियुक्त करती है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायाक्षय के न्यायाधीश श्री व्यास देव मिश्र होंगे जो निम्नलिखित मामलों की जांच करेगा, श्रर्थात :---

- (क) 18 प्रगस्त को श्री भोंकार सिंह की तथाकथित हत्या के बाद 19 भगस्त, 1972 से 22 श्रगस्त 1972 तक शाहदरा और दिल्ली में भ्रन्यज हुए देगों का घटनाकम ;
- (ख) उक्त दंगों को रोकने तथा उनके बारे में कार्रवाई के लिये किये गए प्रशासनिक उपायों की उपयुक्तता ;
- (ग) पुलिस द्वारा बल प्रयोग तथा उसकी प्रमुक्त मान्ना का भौकित्य ;
- (घ) पुलिस द्वारा की गई ज्यादितयों के ग्रारोप यदि कोई हों ; ग्रीर
- (ङ) ग्रन्य कोई मामला जिसका उक्त बातों से सम्बन्ध हो।

यह द्यायोग पूरा प्रयत्म करेगा कि इस जांच को पूरी करके 31 दिसम्बर, 1972 तक केन्द्रीय सरकार के समक्ष भ्रमना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

तथा यतः केन्द्रीय सरकार का मत है कि इस बारे में की जाने वाली जांच की प्रकृति को तथा मामले की घन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच ग्रायोग ग्रिधिनियम, 1952(1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) ग्रीर उपधारा (5) की सभी व्यवस्थाएं उक्त ग्रायोग पर लागू की जानी चाहिए, भौर केन्द्रीय सरकार उक्त धारा (5) की उपधारा (1) के ग्रिधीन एतक्द्रारा निवेश देती है कि पूर्वोक्त सभी व्यवस्थाएं उक्त ग्रायोग पर लागू होंगी।

[सं॰ 31/6/72-भौल-1]

टी० सी० ए० श्रीनिवासबरदन, संयुक्त सवित्र ।